श्री नीतीश कुमार: मैडम, जिन रोगों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, वे कई प्रकार के रोग हैं, लेकिन इन में खास तौर से रिंडर पेस्ट डिसीज के इरेडिकेशन के लिए पूरी योजना चल रही है और एक तरह से भारत ने प्रोवीजनली यह घोषित कर दिया है कि हम अपने यहां से रिंडर पेस्ट डिसीज को समाप्त कर देंगे। इस के बारे में ओ०आई०ई० के पास रिपोर्ट भेजी जा रही है जोकि इन सब चीजों की दो स्तर पर जांच करेगी कि क्या यह रोग चला गया है या बचा है जिस से कभी भी और इनफेक्शन हो सकता है। इस बारे में उम्मीद की जाती है कि अंतिम बात सन् 2000 तक हो पाएगी जब इन के द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उपसभापति जी, जहां तक फूट एंड माऊथ डिसीज का सवाल है, जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, यह जो बीमारी है यह दुनिया भर में है। हमारे यहां इस बीमारी के इलाज के लिए सबसे ज्यादा थ्रस्ट दिया जाता है और इस पर मेडिसिन, वैक्सीन वगैरह की रिसर्च चलती रहती है। अभी तक जो वैक्सीन है, वह 6 महीने तक इफेक्टिव होती है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अब हमने इसमें इजाद कर लिया है और यह 9 महीने तक इफेक्टिव होगी। इस प्रकार से इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है और जो यह मेडिसिन बनाई जाती हैं, वैक्सीन बनाई जाती हैं, उनकी क्वालिटी पर भी ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही प्रोडक्शन पर भी सरकार जो भी संभव सहायता होती है वह करती है।

Withdrawal of NDDB from MAHAPHED

*364. SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Government have decided to withdraw the National Dairy Development Board (NDDB) from MAHAPHED; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House

Statement

(a) and (b) The management of Maharashtra State Co-operative Oilseeds Growers' Federation Limited (MAHAFED) was taken over by NDDB as administrator from 8.4.1997 on a request from the Government of Maharashtra.

NDDB is reluctant to continue as Administrator unless issues relating to autonomy and State support are satisfactorily resolved.

श्री सतीश प्रधान : उपसभापति महोदया, महाराष्ट्र में खासकर के धूलिया, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है और उसके लिए वहां की सरकार ने फार्मर्स के लिए आयल सीड डवलप करने के लिए महाराष्ट्र आयलसीड प्रोडक्शन फेडरेशन का निर्माण किया था। उस फेडरेशन में कुछ गड़बड़ी हुई, यह सच है, हकीकत है। वहां भ्रष्टाचार हुआ, वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था और इसलिए उस फेडरेशन का काम चलाने के लिए, उसका व्यवस्थापन करने के लिए एनडीडीबी को 1997 में इसकी जिम्मेदारी दी गई। एनडीडीबी ने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए मैं उस समय के मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पुराने लोगों को सेलरी नहीं दी जाती थी, वह भी उन्होंने दी।

उपसभापति : आप इतना लंबा सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं आएगा, आपका सवाल ही रह जाएगा।

श्री सतीश प्रधान : मैडम, अभी अचानक एनडीडीबी ने यह निर्णय लिया है और वह विदड्रा होना चाहता है। मंत्री जी इस बारे में जवाब देते हुए बताते हैं कि जब तक स्वायत्तता तथा राज्य सहायता से संबंधित मुद्दों का संतोषप्रद समाधान न हो जाए तब तक उसके साथ नहीं रहना चाहता। मेरा सवाल यह है कि जिस दिन आपने उनके साथ कांट्रेक्ट कर व्यवस्थापन अपने हाथ में लिया, उस समय कुछ टर्मस एंड कंडीशन्स जो रखी थीं, उसमें बदलाव क्यों हो गया? यह बदलाव करने की जरूरत आपको क्यों लगने लगी?

श्री नीतीश कुमार : मैडम, एनडीडीबी ने स्वीकार कर लिया था और जो यह महाराष्ट्र फेडरेशन है उसके संचालन का काम अपने हाथ में ले लिया था। इसका महाराष्ट्र सरकार ने भी अनुरोध किया था और बातचीत हुई थी, जिसके आधार पर इन लोगों ने एनडीडीबी को अपने हाथ में लिया, लेकिन एनडीडीबी ने कुछ शर्तें रखी थीं, जो राज्य सरकार और एनडीडीबी के बीच वार्तालाप हुई थी, उन्हीं शर्तों के हिसाब से एनडीडीबी वहां के फेडरेशन के काम को संचालित करने में पूरी इंडिपेंडेंस चाहती थी। एनडीडीबी ने यह महसूस किया कि बीच के दिनों में उसमें काफी हस्तक्षेप हो रहा है और यह उल्लेख करना मुनासिब नहीं होगा कि किसी एक खास अधिकारी के द्वारा हस्तक्षेप हो रहा था। फिर यह बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद यह रास्ता निकल रहा है कि अब एनडीडीबी राजी है उसको आगे चलाने के लिए, लेकिन उसके बारे में एक जो एग्रीमेंट होना है राज्य सरकार और एनडीडीबी के बीच में, वह अभी तक नहीं हो पाया है।

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

सभापति जी, हम माननीय सदस्य को बताना चाहेंगे कि वह अनुबंध हो जाए, उस पर हस्ताक्षर हो जाएं क्योंकि एनडीडीबी चाहता है कि जो एनडीडीबी को करना है, जो राज्य सरकार को करना है इन दोनों के बीच जो सहमति हुई है, उस सहमति पत्र पर दोनों पक्ष के हस्ताक्षर हो जाएं। इस पर महाराष्ट्र फेडरेशन की भी सहमति है, वहां के आयलसीड ग्रोवर्स की भी सहमति है, सब की सहमति है कि इसे एनडीडीबी चलाए। हमारी भी इच्छा है कि एनडीडीबी चलाए, एनडीडीबी की भी इच्छा है कि उसे एनडीडीबी चलाए, लेकिन एनडीडीबी चाहती है कि पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएं और उनको वहां के काम में स्वायतता मिलनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Child Labour Projects in Andhra Pradesh

*365. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of child labour projects which are in operation through the voluntary agencies in Andhra Pradesh:

(b) the number of child labour under each voluntary agency in the State; and

(c) the results achieved, so far, through these projects?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) Under the Grant-in-aid scheme of the Ministry, voluntary agencies are being financially assisted, on the recommendations of the State Government, to the extent of 75% of the project cost, for taking up action oriented projects for the benefit of children withdrawn from work. These include running of special schools/ centres with provision for non-formal education, supplementary nutrition, health care and vocational/skill training. 6 voluntary